



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २०७]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई २३, १९७५/श्रावण १, १८९७

No. 207]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 1975/SRAVANA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह धलंग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July 1975

G.S.R. 423(E)/IDRA/30/1/75/5.—The following draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 22nd September, 1975.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 1975.

2. In rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, to sub-rule (i) the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that where an application relates to the extension of the period of validity of an industrial licence or the issue of a carry-on-business licence or to diversification within the existing licenced capacity in respect of such scheduled industries as may, from time to time be decided by the Central Government; having regard to the maximisation of production, better utilisation of existing plant and machinery and other factors, the Ministries concerned may dispose of such applications without reference to the Committee.”

[No. F. 14(1)/Lic.Pol./75]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1975

सां. फां. निं. 423 (अ)/आई. डी. आर. ए०/30/1/75/5.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। यह भी ज्ञात रहे कि उक्त प्रारूप पर सितम्बर, 1975 के बाइसवें दिन या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपरोक्त तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आपत्तियां या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1975 है।

2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 10 में, उपनियम (i) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु जहां आवेदन ऐसे अनुसूचित उद्योगों की बाबत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किए जाएं, औद्योगिक अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि के विस्तार के लिए या कारबार चालू रहने की अनुज्ञप्ति जारी रखने के लिए या विद्यमान अनुज्ञप्ति क्षमता के अंतर विधिधीकरण के लिए है वहां सम्बद्ध मंत्रालय ऐसे आवेदन को समिति को निर्देशित किए बिना, अधिकतम उत्पादन, विद्यमान संयंत्र और मशीनों के और अच्छे ढंग से उपयोग तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए स्वयं निपटा सकता है।”

[सं. फां. 14(1)/अनु. नी. 75]

डॉ. के. सक्सेना, संयुक्त सचिव।